



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2015/आश्विन 1, 1937

No. 247]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2015/ASVINA 1, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2015

(अंतिम जाँच परिणाम)

विषय : चीन जन. गण. और यू.एई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हैक्सामाइन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच के अंतिम जाँच परिणाम

संख्या 14/16/2013-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- यतः मै. कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मै. सिमालिन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (जिन्हें एतद्पश्चात आवेदक या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने और चीन जन. गण. और संयुक्त अरब अमीरात (यू.एई) (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित हैक्सामाइन (जिसे एतद्पश्चात विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के, घरेलू उद्योग को क्षति, कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य पाये और इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार दिनांक 25 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. 14/16/2013-डीजीएडी के द्वारा पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की ताकि कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की जाँच की जा सके और कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले पाटन के आरोप वाले आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने के लिए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 मार्च, 2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 14/16/2013-डीजीएडी जारी की।
 - iii. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों/उद्योग एसोसिएशनों (जिनके ब्योरे घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए) को सार्वजनिक सूचना की प्रति के साथ एक पत्र भेजा और पाटनरोधी नियमों के अनुसार विहित समयसीमा के भीतर लिखित में अपने दृष्टिकोण रखने का उन्हें अवसर दिया।
 - iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई थीं। आवेदन अगोपनीय अंश की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई।
 - v. संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को भेजे गए पत्र और निर्यातक प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ-साथ भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थीं और उनसे संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा संबद्ध देशों से अन्य निर्यातकों/उत्पादकों को भी विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया।
 - vi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं:
 - (क) जिनान झियांगरूई कैमिकल कं. लि., नं. 30 जीफैंग रोड, जिनान, शांडोंग, चीन
 - (ख) रूइसिंग ग्रुप कं. लि., कमरा ए-102 कैमिकल मार्किट, नं. 96 साउथ गांग्ये रोड, लिक्सिया जिला, चीन
जिनान हाओयांग कैमिकल कं. लि, हेहुआ ईस्ट रोड, मिंगशुइ, झांगकी सिटी, शांडोंग प्रोविंस, चीन
 - (ग) नानजिंग टिकैम इंडस्ट्री कं. लि., 1804 रूइहुआ मैनसन, 315 झोंगशान नान रोड, नानजिंग, चीन
 - (घ) जिनान शेनयू इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि., - नार्थ आफ लिशान, नार्थ रोड, जिनान, शेंडोंग, 250100, चीन
 - (ङ) अन्हुई ग्रेसमैन इंप एंड एक्स. डेवलपमेंट कं. लि., दि गार्मेट्स मैनसन, नं. 112, लुजिआंग रोड, हेफेइ, अन्हुई-233500
 - (च) जिन डे युआन कैमिकल कं. लि. स्ट्रीट नं. 111 नार्थ सेकंड रिंग रोड, चांगएन एरिया शिजिंझुआंग, हेबेई चीन
 - (छ) जिनान लिचेंग जिनजिंग आकिजिलरी एजेंट फैक्टरी, लिनगांग डेवलपमेंट जोन, याओकिआंग टाउन, लिचेंग जिला, जिनान-250100-चीन
 - vii. चीन जन. गण. से निर्यातकों ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया।
 - viii. प्राधिकारी ने यूएई में किसी ज्ञात निर्यातक को कोई निर्यातक प्रश्नावली नहीं भेजी है क्योंकि घरेलू उद्योग ने यूएई में किसी ज्ञात निर्यातक का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग ने यूएई से पाटित आयातों के प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं इसलिए प्राधिकारी ने नई दिल्ली में यूएई के दूतावास को एक पत्र भेजा था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि “.....संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा शायद प्रत्यक्ष तौर पर सूचित नहीं किया गया था। अतः अनुरोध है कि इस जांच को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। जिन निर्यातकों/आयातकों की भारत के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने की इच्छा है उन्हें इस पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्राधिकारी को संलग्न प्रश्नावली में निर्धारित तौर तरीकों से सूचना प्रेषित करने का परामर्श दिया जाए।”

- ix. यूएई से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। तथापि, इंडस्ट्रियल अफेयर्स विभाग, मिनिस्ट्री आफ इकाॅनामी, यूएई द्वारा एक कानूनी आवेदन भेजा गया था।
- x. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम एवं पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गए थे) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित की तथा उन्हें सलाह दी कि नियम 6(4) के अनुरूप इस पत्र के जारी होने की तिथि से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं:

आयातक/प्रयोक्ता

- (क) शुभम कैमिकल्स एंड सालवेंट्स लि., दिल्ली
- (ख) अशोका मार्केटिंग एजेंसीज, चेन्नई
- (ग) एस्टरकोटे प्रा.लि., चेन्नई
- (घ) गार्गी हटेन्स पी. लि. – एल्बरटस प्रा. लि., मुम्बई
- (ङ) साकेत कैमिकल्स, मुम्बई
- (च) दुजावाला पेपर कैम, मुम्बई
- (छ) आईवीपी लि., जमशेदपुर
- (ज) टी. आर. कैमिकल्स प्रा. लि., राजगनपुर, उड़ीसा
- (झ) एचपीएल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., फरीदाबाद
- (ञ) शिवम अधेसिव्स प्रा. लि. हनुमानगढ जं., राजस्थान
- (ट) आईवीपी लि., पालघर, थाणे
- (ठ) फोसेब्रो इंडिया लि., पुणे
- (ड) नेशनल कैमिकल् इंडस्ट्रीज, कोटा
- (ढ) राजस्थान कोटिंग्स एंड कैमिकल्स, जोधपुर
- (ण) दिमाको पालिमर्स पी. लि., फरीदाबाद
- (त) इंडोगल्फ इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
- (थ) गेटवेल कैम, मुम्बई
- (द) मादीकैम प्लास्ट मैटेरियल्स पी. लि., मुम्बई
- (ध) रूपानी कैमिकल् एजेंसीज, चेन्नई
- (न) एक्स प्रो इंडिया लि., फरीदाबाद
- (त्त) आर्डेनेंस फैक्टरी, नागपुर
- (प) एस.आर. प्लास्टिक्स, दिल्ली
- (फ) रेजिस एंड प्लनास्टिक्स लि., मुम्बई
- (ब) प्रगति कैमिकल्स पी. लि., अंकलेश्वर, गुजरात
- (भ) डी.सी. कैमिकल्स, कोलकाता
- (म) प्रोमिस इंडस्ट्रीज, जमशेदपुर
- (य) पी. कुमार एंड कंपनी, कोलकाता
- (र) टेक्नो वैक्सकैम पी. लि., कोलकाता
- (ल) दुजादवाला पेपरकैम, मुम्बई
- (व) नेशनल टेक्नो इंडस्ट्रीज, कोटा

- (श) ए.वी.एम. सेल्स कार्पो., कोलकाता
- (ष) गुडविल रसायन, मुम्बई
- (स) युनाइटेड मेटा कैम प्रा. लि., पुणे
- xi. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता से प्रश्नावली को कोई उत्तर या कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।
 - xii. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 तक है। हानि संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2010-2011, 201-2012, 2012-2013 तथा जांच की यह अवधि शामिल है।
 - xiii. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्योरो की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया और उक्त सूचना डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त की गई और वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ अपनाई गई थी।
 - xiv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
 - xv. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत तय करने तथा अपनी सतत रीतियों के अनुसार भारत से संबद्ध वस्तुओं का क्षति रहित मूल्य का निर्धारण करने जिससे इस बात की जांच की जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, हेतु नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है।
 - xvi. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 5 जनवरी, 2015 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जिसमें केवल घरेलू उद्योग द्वारा हिस्सा लिया गया। घरेलू उद्योग जिसने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, मौखिक सुनवाई के बाद प्रशासनिक तात्कालिकता के कारण एक नए अधिकारी को निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस घटनाक्रम से यह आवश्यक हो गया कि 7.1.2011 को 2006 की सिविल अपील संख्या 949 में एक डिविजन पीठ द्वारा आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार नए डीए द्वारा नई आम सुनवाई आयोजित की जाए। अतः नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19.08.2015 को पुनः मौखिक सुनवाई की गई जिसमें पुनः केवल घरेलू उद्योग ने ही हिस्सा लिया। घरेलू उद्योग से पुनः मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
 - xvii. इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और यूआई की सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर इस जाँच परिणाम में संगत पाई गई सीमा तक जाँच और उनका समाधान किया गया।
 - xviii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन किया गया था।
 - xix. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध कराएं।
 - xx. जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया या जांच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर इन अनिवार्य तथ्यों को दर्ज की हैं और ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है।
 - xxi. प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जाँच परिणामों का आधार होगा, 08.09.2015 को जारी किया गया था। केवल घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियों प्रस्तुत की जिन पर संगत पाई गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया।
 - xxii. प्राधिकारी के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय द्वारा इस जांच के पूरा होने की मूल तारीख तारीख को 24.09.2015 तक बढ़ा दिया गया था।
 - xxiii. इस निष्कर्ष में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इसी प्रकार मानी गई सूचना का द्योतक है।

xxiv. पीओआई के लिए विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 1 अमरीकी डॉलर = 56.89 रुपये के रूप में लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

4. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद हैक्सा मिथाइलीन टेट्रामाइन है जिसे बाजार की भाषा में हैक्सामाइन के रूप में जाना जाता है।
- ii. हैक्सामाइन का प्रयोग विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों में होता है। हैक्सामाइन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग ठोस फेनोलिक रेजिन्स के उत्पादन के लिए होता है। इसका उपयोग फेनोलफारमेलिडाइड जैसे थर्मोसेटिंग रेजिन्स में भी किया जा रहा है। इसका प्रयोग ठोस बनाने और रेजिन्स के लिए क्रास-लिंगिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है। इन दोनों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय प्रवृत्तियाँ हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता एक-दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं।

ग.2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्ष द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया या कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

6. वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद हैक्सा मिथाइलीन टेट्रामाइन है जिसे बाजार की भाषा में हैक्सामाइन के रूप में जाना जाता है। हैक्सा मिथाइलीन टेट्रामाइन एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है जिसका स्वाद मीठा धात्विक होता है। शुद्ध रूप में, यह रंगहीन और गंधरहित होता है। यह रोम्बिक डाडेकाहेड्रोन्स में क्रिस्टल बनता है। हैक्सा मिथाइलीन टेट्रामाइन यौगिक अम्मोफोर्म, मेथेनामाइन, सिस्टामाइन, सिस्टोजेन, यूरोट्रोपाइन के रूप में भी जाना जाता है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा-शुल्क उप-शीर्ष 2921.29.10 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जॉच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। समान वस्तु के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने रिकार्ड में अनुरोधों की जॉच की है और यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता एक-दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी प्रतिवादी हितबद्ध पक्ष ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. यह याचिका मै. सिमालिन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., वडोदरा और मै. कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. अंकलेश्वर द्वारा संयुक्त रूप से घरेलू उद्योग की ओर से दायर की गई है।
- ii. भारत में विचाराधीन उत्पाद के चार उत्पादक हैं। तथापि, अनेक देशों से उत्पाद के भारी पाटन के कारण अन्य दो उत्पादकों अर्थात् मै. रॉकहार्ड और मै. न्यूटन इंजीनियरिंग का उत्पादन बंद हो गया है। अतः, याचिकाकर्ताओं का उत्पादन नियमावली के अर्थ के भीतर कुल भारतीय उत्पादन बनता है।

घ.2 निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों के विचार

8. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया है या कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

9. प्राधिकारी ने किए गए अनुरोधों की जाँच की है। यह याचिका मै. सिमालिन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., वडोदरा और मै. कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. अंकलेश्वर द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। दोनों कंपनियां भारत में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक हैं और उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार उन्होंने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से उत्पाद का आयात नहीं किया है। वे संबद्ध देशों में किसी उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

10. प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए वे नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और उनके पास इसकी योग्यता है।

पाटन का आकलन – पद्धति और मापदंड**इ.1 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के किसी निर्यातक/उत्पादक ने विहित ढंग और तरीके से निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है।

इ.2 घरेलू उद्योग के विचार

12. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (क) पूर्ववर्ती मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जाँचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए रूख के अनुक्रम में चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- (ख) बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) के दावे को सिद्ध करने के लिए पाटनरोधी नियमावली में विहित कतिपय शर्तों को पूरा करता होता है। भारत और अन्य जाँचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की जाँच से संबंधित विभिन्न निर्णयों के आधार पर कतिपय न्याय शास्त्र स्पष्ट रूप से बना है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करने पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। यह नोट किया जाए कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के लिए आशयित निर्यातक को प्रत्येक शर्त को पूरा करना होगा।
 - i. ऐसी स्थिति में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है जहां एक प्रमुख शेयरधारक कोई राज्य के स्वामित्व वाली/नियंत्रण वाली कंपनी हो।
 - ii. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक प्रतिवादी चीनी निर्यातक यह सिद्ध न कर दें कि प्रमुख निविष्टियों की कीमत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य को दर्शाती है।
 - iii. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न कर दें कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार की जाती है।
 - iv. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब भी नहीं दिया जा सकता यदि इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती हो।
 - v. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा सिद्ध करने का दायित्व/जिम्मेदारी प्रतिवादी चीन निर्यातकों पर है और न कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पर।
 - vi. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से दावा न करें।
 - vii. ऐसी किसी स्थिति में जहां शेयरधारकों ने स्वयं की उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं अपितु किसी अन्य पक्ष से उनका अधिग्रहण किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक रूपांतरण की प्रक्रिया को दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए पूर्णतः सिद्ध न किया जाए।
 - viii. यदि प्रतिवादी चीन निर्यातक इनमें से प्रत्येक मानक को पूरा नहीं करते हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अपेक्षित है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि संबद्ध देशों से किसी निर्यातक या उत्पादक ने जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और निर्यातक प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्यवाही कर सकते हैं।

घ. चीन के उत्पादकों के लिए भारत एक उचित प्रतिनिधि देश है। अन्य जाँचकर्ता प्राधिकारियों ने भी इसे स्वीकार किया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रमुख कच्ची सामग्री (फारमेल्डिहाइड) की कीमत और खपत मानकों और सभी अन्य कच्ची सामग्री की लागतों,

सुविधा और परिवर्तन लागत के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन गण में सामान्य मूल्य का दावा किया है। कच्ची सामग्री की कीमत में भारी वृद्धि जिसकी वजह से उत्पाद की संबद्ध लागत में भारी वृद्धि हुई है को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने माह-वार पाटन मार्जिन की गणना के लिए माह-वार सामान्य मूल्य के परिकलन का दावा किया है।

ड. याचिकाकर्ताओं ने यूआई के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने का और प्रकाशित स्रोतों से कीमत का साक्ष्य लेने का प्रयास किया है। तथापि, वे सावर्जनिक डोमेन में संगत सूचना के अभाव के कारण यूआई के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की कीमत सूची या उद्धरण जैसी सूचना/साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने यूआई से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का परिकलन डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों से ले गई कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और घरेलू उद्योग के खपत मानकों, परिवर्तन लागत के अनुमानों, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर किया है। कच्ची सामग्री की कीमत में भारी वृद्धि जिसकी वजह से उत्पाद की संबद्ध लागत में भारी वृद्धि हुई है को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने माह-वार पाटन मार्जिन की गणना के लिए माह-वार सामान्य मूल्य के परिकलन का दावा किया है।

च. याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर-देशीय भाड़ा, बैंकप्रभारों, कमीशन और वैट (चीन जन गण के मामले में) के लिए व्ययों को समायोजित किया है।

छ. उक्त आधारों पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करने के बाद दोनों संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

ड. 3 चीन जन. गण. के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में चीन जन गण को डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा भी पाटनरोधी जाँचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) के अनुसार चीन जन गण को उक्त नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उक्त धारणा के खंडन के अधीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।

14. यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, के अनुबंध-क के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जा सके कि क्या :-

- क. कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
- ख. इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;
- ग. इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- घ. विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

15. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-न के पैरा-7 में उपबंध है कि:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

16. चीन जन गण के किसी निर्यातक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से संबंधित प्रश्नावली और निर्यातक प्रश्नावली, प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जॉच शुरुआत संबंधी सूचना के परिणामस्वरूप उत्तर नहीं दिया और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन नहीं किया है।

17. इस तथ्य को देखते हुए कि किसी उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी प्रश्नावली सहित किसी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, चीन के उत्पादकों को एमईटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्ष ने किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के लिए प्राधिकारी को कोई वास्तविक तथ्य उपलब्ध नहीं कराया है। अतः प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार अन्य तर्कसंगत आधार पर चीन जन गण के संबंध में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

18. तदनुसार, चीन जन गण से सभी निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद का कारखाना द्वार सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिकलित किया गया है और प्राधिकारी ने चीन जन गण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के दूसरे परंतुक के अनुसार “किसी अन्य तर्कसंगत आधार” को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। चीन जन गण के संबंध में कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए माह-वार परिकलित लागत के आधार पर किया गया है। कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को अपनाकर और अति सक्षम घरेलू उत्पादक की लागत के आधार पर और उचित लाभ प्रदान करके सामान्य मूल्य आकलित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित भारित औसत परिकलित सामान्य मूल्य को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

इ. 4 यूई के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूई से किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार यूई के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाध्य हैं। तदनुसार, यूई के संबंध में कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए माह-वार परिकलित लागत के आधार पर किया गया है। कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को अपनाकर और अति सक्षम घरेलू उत्पादक की लागत के आधार पर और उचित लाभ प्रदान करके सामान्य मूल्य आकलित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित भारित औसत परिकलित सामान्य मूल्य को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

इ. 5 चीन जन. गण. के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

20. चूंकि चीन जन गण से किसी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन गण से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत को निर्धारित किया है।¹ याचिकाकर्ताओं ने आकड़े प्रदाता एजेंसी आईबीआईएस द्वारा यथा सूचित भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के आधार पर निर्यात कीमत को निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने डीजीआईएंड एस से सौदा-वार आयात आकड़ों को प्राप्त किया है। यह देखा जाता है कि डीजीसीआईएंडएस और आईबीआईएस दोनों द्वारा सूचित आयात कीमतें तुलनीय हैं। तथापि, डीजीसीआईएंडएस द्वारा बताई गई आयातों की मात्रा उच्चतर है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आकड़ों पर विचार किया है और भारत में विचाराधीन उत्पाद के समस्त आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की है। चीन जन गण से निर्यातकों के असहयोग के कारण आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर कीमत संबंधी समायोजन किए गए हैं। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक प्रभारों, वैट, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़ा व्ययों के लिए कीमत संबंधी समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित कारखाना-द्वार निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

इ. 6 यूई के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

21. चूंकि यूई से किसी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन गण से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत को निर्धारित किया है। याचिकाकर्ताओं ने आकड़े प्रदाता एजेंसी आईबीआईएस द्वारा यथा सूचित भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के आधार पर निर्यात कीमत को निर्धारित किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीआईएंड एस से सौदा-वार आयात आकड़ों को प्राप्त किया है। यह देखा जाता है कि डीजीसीआईएंडएस और आईबीआईएस दोनों द्वारा सूचित आयात कीमतें तुलनीय हैं। तथापि, डीजीसीआईएंडएस द्वारा बताई गई आयातों की मात्रा उच्चतर है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आकड़ों पर विचार किया है और भारत में विचाराधीन उत्पाद के समस्त आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की है। यूई से निर्यातकों के असहयोग के कारण आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर कीमत संबंधी समायोजन किए गए हैं। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक प्रभारों, वैट, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़ा व्ययों के लिए कीमत संबंधी समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित कारखाना-द्वार निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

इ. 7 पाटन मार्जिन

22. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए प्रस्तावित पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है।

पाटन मार्जिन तालिका

मापदंड	इकाई	चीन	यू.ए.
सामान्य मूल्य	अम.डा./एमटी	***	***
निर्यात कीमत	अम.डा./एमटी	***	***
पाटन मार्जिन	अम.डा./एमटी	***	***
पाटन मार्जिन %	अम.डा./एमटी	***	***
पाटन मार्जिन %	%	5-15	5-15

इ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध की जाँच**च. 1 घरेलू उद्योग के विचार**

23. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि :

- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं।
- संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बनाए हुए हैं और ऐसी कीमत वृद्धि का रोक रहे हैं जो पाटन के अभाव में बढ़ गई होती।
- घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, माल सूचियों, बाजार हिस्से, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह की दृष्टि से तेजी से गिरावट आई है और ये ऋणात्मक स्तर पर पहुंच गए हैं।
- उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन खराब रहा है।
- पाटन मार्जिन काफी अधिक है।
- घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक पाटित स्रोतों से आयात कीमतें हैं। इस प्रकार कीमत ह्रास बाजार में उत्पाद के पाटन के कारण हुआ है।
- संबद्ध देशों से पाटित आयातों के अलावा, पाटनरोधी शुल्क वाले मौजूदा स्रोतों से आयातों के कारण भी क्षति हो रही है।
- अनेक मापदंडों के अनुसार घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकूल रही है।

च. 2 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

24. इंडस्ट्रियल अफेयर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री आफ इकाॅनामी, यू.ए. ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- निर्दिष्ट प्राधिकारी पर आवश्यक प्रक्रिया के दायित्व के अनुसार यू.ए. को उसके अधिकारों की रक्षा करने का पूरा अवसर देना जरूरी है।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह अवश्य दर्शाना चाहिए कि घरेलू समान उत्पाद को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है। अगोपनीय आकड़े 2013 में 12 प्रतिशत की समग्र कमी (2012 में 1439 के बजाय 2013 में 1239 एमटी) और घरेलू उद्योग के उत्पादन के अनुसार 1 प्रतिशत और विचाराधीन उत्पाद की खपत के अनुसार 1 प्रतिशत तक की कमी दर्शाते हैं। अतः इसकी संभावना नहीं है कि संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, जो घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं, पर संबद्ध देशों से आयात के किसी अन्य पर्याप्त प्रभाव के लिए संबद्ध देशों से आयातों को जिम्मेदार ठहराया जाए।
- यू.ए. मानता है कि संबंधित घरेलू उत्पाद को क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं अपितु अन्य कारणों की वजह से हुई है।
- 2011-12 समय अवधि के दौरान जब मात्रा में 331 एमटी से 1,088 एमटी की वृद्धि हुई, तो घरेलू उद्योग ने ने क्षमता, उत्पादन, रोजगार, मजदूरी और घरेलू बिक्रियों की दृष्टि से अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया।
- पाटनरोधी शुल्क वाले देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को कथित क्षति उठानी पड़ी है। ईरान, रूस और सऊदी अरब किंगडम पर यद्यपि हैक्सामाइन पर शुल्क लागू है परंतु उन्होंने समग्र रूप से अपने निर्यातों में 77.5 प्रतिशत और घरेलू उद्योग के उत्पादन के सापेक्ष 4 प्रतिशत की वृद्धि की है।

- (च) ऐसे देशों जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है से आयातों का बाजार हिस्सा 2012 में 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 7 प्रतिशत हो गया है और विचाराधीन उत्पाद के आयातों में 2013 में 27 से 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- (छ) मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कथित क्षति हो रही है। जाँच अवधि के आकड़े दर्शाते हैं कि मांग में 5.2 प्रतिशत की कमी आई है जो 13780 एमटी से घटकर 13,060 एमटी रह गई है।
- (ज) निर्दिष्ट प्राधिकारी पर अपने जाँच परिणामों को सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित करने और वस्तुनिष्ठ जाँच करने का डब्लूटीओ संबंधी उत्तरदायित्व है।

दूसरी मौखिक सुनवाई के बाद के अनुरोध

25. दूसरी मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और वे दोहराये गए हैं अर्थात् संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और न्यूनीकरण हो रहा है, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, लाभ, निवेशों पर आय, नकद प्रवाह आदि की दृष्टि से तेजी से गिरावट आई है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अनुरोध दोहराये गए हैं और प्रकटन विवरण के संगत शीर्षों में उन पर विचार किया गया है।

च. 3 संचयी मूल्यांकन

27. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा
- ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

28. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन ऊपर विहित सीमाओं से काफी अधिक है।
- ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा ऊपर विहित सीमाओं से अधिक है।
- iii. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जारी वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

29. इस संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करते हैं।

30. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

31. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच के लिए संबंधित नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर विचार किया गया है।

32. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

(i). प्राधिकारी मानते हैं कि यूएई को उसके अधिकारों की रक्षा करने का अवसर दिया जाना आवश्यक प्रक्रियागत दायित्व है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय नियमों और डब्लूटीओ दायित्वों के अनुसार सभी आवश्यक प्रक्रियागत दायित्वों का वर्तमान जॉच में अनुपालन किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यूएई के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने न तो प्रश्नावली का उत्तर देकर सहयोग किया है और न ही वर्तमान जॉच में संगत सूचना प्रदान की है।

(ii). इस तर्क के संबंध में कि यह सिद्ध किया जाए कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है और यूएई से उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से कमी आई है प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन और यूएई से आयातों के संबंध में क्षति संबंधी विश्लेषण संचयी रूप से किया गया है। किसी पक्ष द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया है कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के लिए क्षति का संचयी आकलन करना अनुचित है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में 2010-11, 2011-12, 2012-13 और क्षति अवधि के रूप में जॉच अवधि पर विचार किया है और इसलिए कोई भी विश्लेषण क्षति जॉच अवधि पर विचार करते हुए होना चाहिए। पीओआई की तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष से चयनित रूप से तुलना करना उचित नहीं होगा।

(iii). इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों की वजह से और न कि पाटित आयातों के कारण हुई है प्राधिकारी ने कानून के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों की जॉच की है। प्राधिकारी ऐसे किसी अन्य कारक से वाकिफ नहीं हैं जिसकी वजह से उसी समय क्षति हो सकती हो और न ही किसी हितबद्ध पक्ष ने ऐसे किसी अन्य कारक की मौजूदगी को सिद्ध किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(iv). इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को अन्य स्रोतों जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य स्रोतों से पाटित आयातों से क्षति को नियमों के अंतर्गत अलग किए जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय नियम और डब्लूटीओ करार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अपाटित आयातों की मात्रा और कीमत से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करने का स्पष्ट उल्लेख करते हैं।

(v). इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी पर उनके जॉच परिणामों को सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित करना और उसमें वस्तुनिष्ठ जॉच करने का दायित्व है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्लूटीओ दायित्वों का विधिवत रूप से पालन किया गया है।

33. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों और कीमतों और लाभप्रदतापर उसके प्रभाव की जॉच की है ताकि क्षति की मौजूदगी और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की जॉच की जा सके। प्राधिकारी ने मै. सिमालिन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मै. कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि., जो नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं, से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जॉच की है। तदनुसार, पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभाव की निम्नानुसार जॉच की गई है:

क. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

क) मांग और बाजार हिस्से का आकलन

34. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के योग के रूप में मांग को निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

भारत में मांग		2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	10,453	11,550	11,849	10,905
आयात-संबद्ध देश	एमटी	409	1,270	1,343	1,300
आयात-देश जिनपर एडीडी लागू है	एमटी	727	600	575	1,108
आयात-अन्य देश	एमटी	0	241	44	264
कुल मांग	एमटी	11,589	13,661	13,810	13,577
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	90.19%	84.55%	85.80%	80.32%
संबद्ध देश	%	3.53%	9.29%	9.72%	9.58%
देश जिन पर एडीडी लागू है	%	6.28%	4.39%	4.16%	8.16%
अन्य देश	%	0.00%	1.76%	0.32%	1.94%

• पीओआई- अक्टूबर 2012 – सितम्बर 2013

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में संबंधित उत्पाद के लिए मांग में आधार वर्ष से 2012-13 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद पीओआई में मामूली गिरावट आई है। तथापि, पीओआई में मांग में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भी 2012-13 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद पीओआई में कमी आई है। संबद्ध देशों से आयातों में भी यही रुझान रहा है।

36. उक्त तालिका से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि यह कि संबद्ध देशों तथा पाटनरोधी शुल्क लागू वाले देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

ख) पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव: आयात मात्राएं और बाजार हिस्सा

37. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। आयातों की मात्रा और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
आयात-चीन	एमटी	409	750	494	640
आयात-यूएई	एमटी	0	520	849	660
आयात-संबद्ध देश	एमटी	409	1,270	1,343	1,300
आयात-देश जिनपर एडीडी लागू है	एमटी	727	600	575	1,108
आयात-अन्य देश	एमटी	0	241	44	264
कुल आयात	एमटी	1,136	2,111	1,962	2,672
निम्न के संबंध में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा					
कुल आयात	%	35.99%	60.15%	68.44%	48.65%
खपत	%	3.53%	9.29%	9.72%	9.58%
उत्पादन	%	3.79%	10.03%	10.94%	11.02%

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- यूएई से संबद्ध वस्तु के आयात 2011-12 में शुरू हुए और क्षति अवधि के दौरान तक काफी अधिक बने रहे। चीन जन. गण. से आयातों में क्षति अवधि के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।
- यद्यपि संचयी आधार पर संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पीओआई में गिरावट आई है तथापि, वह अब भी काफी अधिक है और 2010-11 और 2011-12 में आयातों की मात्रा से अधिक हैं।
- संबद्ध आयातों में न केवल समग्र रूप से वृद्धि हुई है अपितु भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है और जाँच अवधि में मामूली गिरावट आई है।
- यद्यपि जाँच अवधि में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में गिरावट आई है तथापि, वह अब भी काफी अधिक है और 2010-11 और 2011-12 में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों की मात्रा से अधिक हैं।
- इस तर्क के संबंध में कि चूंकि आयात न तो समग्र रूप से या न ही उत्पादन या खपत की दृष्टि से बढे हैं और इस बात की संभावना नहीं है कि घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संगत आर्थिक कारकों पर संबद्ध देशों से आयातों के किसी अन्य पर्याप्त प्रभाव के लिए संबद्ध देशों से आयातों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, या घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, रोजगार, मजदूरी और घरेलू बिक्रियों के संबंध में अपने कार्यनिष्पादन में जब सुधार किया जब यूएई से आयातों में वृद्धि प्रदर्शित हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के समग्र कार्यनिष्पादन में क्षति अवधि के दौरान वास्तविक विकृति प्रदर्शित हुई है।

ख. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**क) कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री**

39. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत मंदी के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश के आयातों के पंधुच मूल्य के साथ की गई है। जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों के पंधुच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के निर्धारण में करों, बट्टों, छूटों और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कमीशन को समायोजित किया गया है। कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है आई इसलिए प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत ज्ञात की है और कम कीमत पर बिक्री निकालने के लिए उसकी तुलना पंधुच मूल्य के साथ की है। घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का मूल्यांकन पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन लागत पर उचित ढंग से विचार करने के बाद किया गया है। स्थिति निम्नानुसार है:

कीमत कटौती

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
निवल बिक्री प्राप्ति	रूपये/एमटी	***	***	***	***
आयातों का पंधुच मूल्य – चीन	रूपये/एमटी	48,530	55,042	70,926	68,173
आयातों का पंधुच मूल्य – यूएई	रूपये/एमटी	0	52,629	65,076	57,671
पंधुच मूल्य – संबद्ध देश समग्र रूप से	रूपये/एमटी	48,530	54,053	67,226	62,841
कीमत कटौती – चीन	रूपये/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती – यूएई	रूपये/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती – संबद्ध देश समग्र रूप से	रूपये/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती – चीन	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-10%	5-15%	(0-10)%	0-10%
कीमत कटौती – यूएई	%	***	***	***	***
रेंज	%	-	10-20%	0-10	15-30%
कीमत कटौती – संबद्ध देश समग्र रूप से	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-10%	10-20%	0-10%	5-15%

कम कीमत पर बिक्री

विवरण	इकाई	चीन	यूएई
क्षतिरहित कीमत	अम.डा./एमटी	***	***
आयातों का पंधुच मूल्य	अम.डा./एमटी	1,199.60	1,022.58
कम कीमत पर बिक्री	अम.डा./एमटी	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
रेंज	%	0-10	15-25

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों संबद्ध देशों से कीमत कटौती काफी अधिक है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों का पंधुच मूल्य भी घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम है, इस प्रकार परिणामस्वरूप भारी कम कीमत पर बिक्री प्रभाव पड़ा है जैसा भारित औसत आधार पर कम कीमत पर बिक्री के स्तर से देखा जाता है जिसे कच्ची सामग्री की कीमतों में भारी वृद्धि जिससे उत्पाद की संबद्ध लागतों और कीमत में भारी वृद्धि हुई को देखते हुए माह-वार आधार पर परिकलित किया गया है।

ख) कीमत ह्रास और मंदी

41. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत ह्रास और मंदी प्रभावों की जाँच के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के रुझान की तुलना बिक्री लागत के साथ की गई है। आकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 2011 के बाद और पीओआई तक बिक्री लागत से कम रही है, जिससे कीमत ह्रास प्रभाव की मौजूदगी का पता चलता है। इस संबंध में रुझानों का सारांश नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
बिक्री कीमत	रूपये/एमटी	***	***	***	***
रुझान		100	121	135	139
बिक्री लागत	रूपये/एमटी	***	***	***	***
रुझान		100	141	154	163
आयातों का पंधुच मूल्य					
चीन	रूपये/एमटी	48,530	55,042	70,926	68,173
रुझान	रूपये/एमटी	100	113	146	140
यू.एई	रूपये/एमटी	0	52,629	65,076	57,671
रुझान		-	100	124	110

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि में बढ़ती रही है। तथापि यह वृद्धि उसी अवधि के दौरान बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं रही है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कच्ची सामग्री की लागत में भारी वृद्धि हुई है जिससे क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 2011 के बाद से पीओआई तक बिक्री लागत से कम रही थी। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों का पंधुच मूल्य भी आधार वर्ष की तुलना में बढ़ा है। तथापि, पंधुच मूल्य में वृद्धि बिक्री लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि से कम रही है। इसके अलावा, आयातों का पंधुच मूल्य 2011-12, 2012-13 और पीओआई के दौरान बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग की घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव डाल रहे हैं।

ग. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

43. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

44. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

45. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राओं संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
क्षमता	एमटी	10,800	17,600	17,600	17,600
उत्पादन	एमटी	10,779	12,660	12,273	11,800
क्षमता उपयोग	%	99.80%	71.93%	69.73%	67.04%
घरेलू बिक्रियां	एमटी	10,453	11,550	11,849	10,905
मांग	एमटी	11,589	13,661	13,810	13,577

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 2011-12 में संबंधित उत्पाद के उत्पादन की स्थापित क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2011-12 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद 2012-13 और पीओआई में कमी आई है। यह नोट किया जाता है क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद घरेलू बिक्री मात्राओं में पीओआई में कमी आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान कमी आई है। इस प्रकार उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्राओं और क्षमता उपयोग में पीओआई में गिरावट आई है।

47. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग ने पहले की उपलब्धि की तरह पीओआई में क्षमता उपयोग की उपलब्धि को प्राप्त कर लिया होता। अनुबंध-III से इस व्याख्या को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया उत्पादन का परिमाण घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली मात्रा से काफी कम था। इस प्रकार आयातों से प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है।

48. याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि विचाराधीन उत्पाद की मांग और घरेलू उद्योग की क्षमताओं पर विचार करते हुए देश में किसी आयात की कोई जरूरत नहीं थी और घरेलू उद्योग ने बाजार की पूरी मांग को पूरा कर दिया होता। तथापि, विदेशी उत्पादकों ने पाटन किया जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

ख) लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ

49. घरेलू उद्योग के लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ की निम्नानुसार जाँच की गई है:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
बिक्री लागत	रूपये/एमटी	****	****	****	****
रुझान	रूपये/एमटी	100	141	154	163
बिक्री कीमत	रूपये/एमटी	****	****	****	****
रुझान	रूपये/एमटी	100	123	135	141
लाभ/हानि (प्रति इकाई)	रूपये/एमटी	****	****	****	****
रुझान	रूपये/एमटी	100	-62	-55	-77
लाभ/हानि कुल	लाख रूपये	****	****	****	****
रुझान	लाख रूपये	100	-69	-62	-80
व्याज पूर्व लाभ	लाख रूपये	****	****	****	****
रुझान	लाख रूपये	100	-47	-37	-49
नकद लाभ	लाख रूपये	****	****	****	****
निवेशों पर आय	%	100	-52	-45	-61
रुझान	%	****	****	****	****

50. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दानों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से कम रही थी। इससे लाभप्रदता में भारी गिरावट आई और अंततः 2011-12 से वित्तीय घाटों की स्थिति आई।
- व्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है और उनमें लाभ की तरह का रुझान रहा।
- याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय बाजार में पाटित आयातों की निरंतर मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने के लिए लागत से कम कीमत पर वस्तुओं को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुपात में उसकी कीमतों में वृद्धि करने से रोका गया है।
- उक्त सूचना से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग लाभ संबंधी मापदंडों के अनुसार क्षति झेलता रहा है। इन मापदंडों के संबंध में उद्योग की स्थिति जाँच अवधि के दौरान काफी बिगड़ गई है।

ग) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

51. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तरों और मजदूरी की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
रूझान	सूचीबद्ध	100	127	130	128
मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***
रूझान	सूचीबद्ध	100	127	135	144
प्रति टन उत्पादन की मजदूरी	रुपये	***	***	***	***
रूझान	सूचीबद्ध	100	108	118	132
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
रूझान	सूचीबद्ध	100	93	87	86

52. उक्त से यह नोट किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में उत्पादन में गिरावट के बाद गिरावट आई है। इसके अलावा, प्रति इकाई मजदूरी लागत में वृद्धि हुई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि इस तथ्य को देखते हुए कि घरेलू उद्योग के घटक बहु-उत्पाद कंपनियां हैं, ये मापदंड पाटन के वर्तमान और संभावित प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शा सकते हैं।

घ) मालसूची

53. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर की जाँच है जिसे निम्नांकित तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
रूझान	सूचीबद्ध	100	203	317	439

54. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि समग्र रूप से औसत मालसूची में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। क्षति अवधि के दौरान औसत मालसूची में चार गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ऐसा वर्तमान और मौजूदा स्रोतों से भारी पाटन की वजह से हुआ है।

ङ) पाटन की मात्रा

55. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकने की क्षमता के रूप में पाटित आयातों की सीमा के संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा दर्शाती है कि संबद्ध देशों के विरुद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।

च) पूंजी जुटाने की क्षमता

56. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के घटक बहु-उत्पाद कंपनियां हैं। निवेश जुटाने की क्षमता समग्र व्यवसायिक प्रचालनों को दर्शाती है और वह उत्पाद विशेष के कार्यनिष्पादन पर निर्भर नहीं होती है।

छ) वृद्धि

57. घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)		2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
उत्पादन मात्रा	एमटी	-	17.45	-3.06	-3.85
घरेलू बिक्री मात्रा	एमटी	-	10.50	2.59	-7.97
लाभ/ हानि	रू./एमटी	-	-162.31	-11.90	-39.46
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	***	***	***
बाजार हिस्सा	%		-5.64%	1.25%	-5.48%

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत मापदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री मात्रा, नकद लाभ और निवेशों पर आय के अनुसार नकारात्मक वृद्धि जर्न की है। लाभप्रदता में गिरावट आई है जैसा कि लाभ, नकद लाभ, और निवेशों पर आय जैसे मापदंडों से देखा जा सकता है। इसके अलावा, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा और मालसूची का स्तर नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि प्रतिकूल रही थी।

ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

59. संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात कीमतों की जाँच, लागत संचरना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा पाटित आयातों से इतर कारक जो संभवतः घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हों दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पंधुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम रहा है, जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में पीओआई के दौरान भारी वृद्धि हुई है और इसलिए उससे घरेलू कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इस प्रकार घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों और अन्य पाटन करने वाले देशों से संबद्ध वस्तु का पंधुच मूल्य है।

60. आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना से नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान बिक्री लागत में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, कच्ची सामग्री की लागत में ही आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, 2011-12 की तुलना में पीओआई के दौरान यूआई से निर्यात कीमत में केवल 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि आधार वर्ष में यूआई से कोई आयात नहीं हुए थे। इसके अलावा चीन से निर्यात कीमत आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान 39 प्रतिशत बढ़ी थी।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

61. पूर्वोक्त को देखते हुए, यह निष्कर्ष प्रस्तावित है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और ऐसी कीमत वृद्धि को रोक रहे हैं जो पाटन के अभाव में बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, मालसूचियों, बाजार हिस्से, लाभों, निवेशों पर आय, नकद प्रवाह की दृष्टि से तेजी से गिरावट आई है और वह नकारात्मक स्तर पर पंधुच गए हैं। घरेलू उद्योग की कार्यनिष्पादन उत्पादन और घरेलू बिक्रियों के संबंध में खराब रहा था। पाटन मार्जिन काफी अधिक है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभावित करने वाले कारक पाटित स्रोतों से आयात कीमते हैं। इस प्रकार, बाजार में उत्पाद के पाटन के कारण कीमत ह्रास हुआ है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के अलावा, मौजूदा स्रोतों जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है से आयातों के कारण भी क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक मापदंडों के अनुसार प्रतिकूल है।

62. अतः यह देखा गया है कि समग्र रूप से और भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है। भारत में समान उत्पादन की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है और ऐसे पाटित आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है और ऐसे कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का परिणामी प्रभाव प्रतिकूल था जो विभिन्न संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय, क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारकों, पाटन की मात्रा और मार्जिन, नकद लाभ (नकद प्रवाह), मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता के समग्र और संचयी आकलन द्वारा भी सिद्ध होता है। इस प्रकार इस निष्कर्ष का प्रस्ताव है कि घरेलू उद्योग को मौजूदा स्रोतों के साथ-साथ चीन और यूआई से पाटन के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।

च.5 अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

63. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है जो निम्नानुसार है:

(क) मांग में संकुचन और/या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की मांग में पीओआई में मामूली गिरावट को छोड़कर क्षति अवधि में वृद्धि होती रही है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है। इसके अलावा प्राधिकारी को उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में किसी परिवर्तन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

65. इस दलील के संबंध में कि उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और उससे भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की समग्र मांग में वृद्धि हुई है तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में मांग में मामूली गिरावट को मांग में गिरावट नहीं माना जा सकता है। संबद्ध देशों से बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान 3.53 प्रतिशत से 9.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान 90.19 प्रतिशत से 80.32 प्रतिशत की कमी आई है।

(ख) पाटित कीमत पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के अलावा, सऊदी अरब और रूस (पाटनरोधी शुल्क लागू) से देश में हैक्सामाइन के आयात प्रवेश कर रहे हैं।

(ग) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है। इसके अलावा, स्वाभाविक रूप से बाजार अर्थव्यवस्था के अलावा घरेलू उत्पादकों के बीच कोई बोधगम्य प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के लिए एकमात्र बाजार है जिसमें संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं और समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों के लिए प्रयुक्त होती हैं। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के बीच ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद या उसके विनिर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी में कोई विकास नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

(ङ) निर्यात कार्यानिष्पादन

69. घरेलू उद्योग के निर्यात का निष्पादन नीचे सारणी में दिया गया है। तथापि, क्षति के संबंध में सूचना की घरेलू प्रचालनों के लिए यथासंभव अलग से जांच की गई है और इसीलिए घरेलू उद्योग के निर्यात का निष्पादन निर्धारित की गई क्षति के लिए कोई संभव कारण नहीं है।

विवरण		2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
निर्यात विक्रियां	एमटी	***	***	***	***

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में अत्यधिक पाटन के कारण उत्पादन में वृद्धि करने में घरेलू उद्योग के असमर्थ होने के कारण गिरावट आई है। अतः उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा सुझाई गई क्षति के लिए प्रत्यक्ष कारण नहीं हो सकती।

का कारण नहीं हो सकता है।

(छ) अन्य उत्पादों का कार्यानिष्पादन

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादकों का निष्पादन पायी गई क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है क्योंकि इस जाँच में समान वस्तु के संबंध में सभी मापदंडों की जाँच की गई है।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि ऊपर सूचीबद्ध जात अन्य कारकों से निर्धारित क्षति हुई प्रतीत नहीं होती है तथापि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

- (i) संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने भारतीय बाजार में भारी मात्रा में प्रवेश किया है और क्षति अवधि में उनमें वृद्धि हुई है।
- (ii) संबद्ध आयात घरेलू कीमतों से कम कीमत पर उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप उपभोक्ता आयातों को अपना रहे रहे हैं इस प्रकार घरेलू उद्योग को कम कीमत रखने पर बाध्य होना पड़ा है। चीन जन गण और यूएई से आयातों से भारी कीमत कटौती हुई है।
- (iii) घरेलू बिक्रियां मांग से तालमेल नहीं रख सकी हैं और घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा गंवाता रहा है।
- (iv) आयात कम और पाटित कीमतों पर हो रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभों, निवेशों पर आय और नकद प्रवाह की दृष्टि से नुकसान हुआ है।
- (v) आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण बाजार में कीमत ह्रास का सामना करना पड़ रहा है।

च.6 क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र रूप से और भारत में स्पष्ट खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्रा में क्षति अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के लाभ-संबंधी मापदंड समग्र रूप से काफी खराब रहे हैं। जाँच अवधि में मालसूची का स्तर काफी अधिक रहा है।

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन और यूएई से आयात शुरू होने से पहले भी घरेलू उद्योग को अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण क्षति हो रही थी। इन आयातों की जाँच की गई और पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। तथापि, इस जाँच में विशेष रूप से पाई गई कीमत कटौती और कीमत ह्रास के कारण यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयात भी अन्य मौजूदा स्रोतों के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।

च.7 क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

75. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। घरेलू उद्योग की इस क्षतिरहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। क्षति मार्जिन निम्नानुसार ज्ञात किया गया है:

क्षति मार्जिन

विवरण	इकाई	चीन	यूएई
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	अम.डा./एमटी	***	***
पहुंच मूल्य	अम.डा./एमटी	1,199.60	1,022.58
क्षति मार्जिन	अम.डा./एमटी	***	***
क्षति मार्जिन %	%	***	***
क्षति मार्जिन रेंज %	%	0-10	15-25

76. यथा निर्धारित क्षति मार्जिनो का स्तर काफी अधिक माना गया है।

हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोध**प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोध**

77. किसी भी प्रतिवादी हितबद्ध पक्ष ने कोई प्रकटन विवरण के बाद का लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोध

78. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोध:

- (क) भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात इसकी सामान्य कीमत से कम कीमत पर किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से पाटन होता है।
- (ख) जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, दोनों महत्वपूर्ण और सकारात्मक होते हैं।
- (ग) घरेलू उद्योग को भारी क्षति का समाना करना पड़ा है।
- (घ) पाटनरोधी शुल्क निश्चय ही स्थायी रूप में लगाया जाता है और शुल्क को यूएस डॉलर में व्यक्त किया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

79. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उक्त तर्कों की जाँच की है और यह पाया है कि वे दोहराये गये हैं और उन पर पूर्व में प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने पहले ही विचार किया है और संगत समझे गए अनुरोधों पर अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना में पुनः विचार किया जा रहा है।

निष्कर्ष

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. और यूएई के किसी भी निर्यातक तथा भारत में आयातकों/ उपयोक्ताओं और अन्य प्रतिवादी इच्छुक पक्षकारों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया। तथापि उठाई गई आपत्तियों के संबंध में मिनिस्ट्री आफ इकॉनामी, यूएई द्वारा विधिक अनुरोध किए गए हैं। उठाई गई आपत्तियों, प्रदान की गई सूचना और घरेलू उद्योग एवं मिनिस्ट्री आफ इकॉनामी, यूएई

द्वारा किए गए अनुरोध तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और उपरोक्त विश्लेषणों तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत दिए गए विवरण को ध्यान में रखकर प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया कि :

(क) जांच की अवधि में संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, दोनों महत्वपूर्ण और सकारात्मक होते हैं।

(ख) घरेलू उद्योग को भारी क्षति का सामना करना पड़ा है।

सिफारिशें

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी और पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं परिणामी क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी नीचे दिए गए ढंग और तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

82. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित राशि के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.स.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1.	2921.29.10	हैक्सामाइन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई	कोई	84.25	एमटी	अम. डा.
2.	2921.29.10	हैक्सामाइन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. से इतर कोई और देश	कोई	कोई	84.25	एमटी	अम. डा.
3.	2921.29.10	हैक्सामाइन	संबद्ध देशों से इतर कोई और	चीन जन. गण.	कोई	कोई	84.25	एमटी	अम. डा.
4.	2921.29.10	हैक्सामाइन	यूएई	यूएई	कोई	कोई	113.05	एमटी	अम. डा.
5.	2921.29.10	हैक्सामाइन	यूएई	यूएई से इतर कोई और देश	कोई	कोई	113.05	एमटी	अम. डा.
6.	2921.29.10	हैक्सामाइन	संबद्ध देशों से इतर कोई और	यूएई	कोई	कोई	113.05	एमटी	अम. डा.

स्पष्टीकरण : जहां विभिन्न सीमा शुल्क संबंधी अधिसूचनाओं में किसी संबद्ध देश के संबंध में संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क में दोहरापन है वहां उस संबद्ध देश के लिए लागू शुल्क, ऐसी सीमा शुल्क संबंधी अधिसूचना के तहत लगाया गया शुल्क होगा जिसमें कि संबद्ध देश को विशेष रूप से “मूलता का देश” कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है।

83. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे।

84. केन्द्र सरकार द्वारा इस जांच परिणाम पर आधारित आदेश के विरुद्ध खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2015

(FINAL FINDINGS)

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Hexamine originating in or exported from China PR and UAE.

No. . 14/16/2013-DGAD —Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof:

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited and M/s Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the applicants or the Domestic Industry) filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ad Rules or the Rules), alleging dumping of Hexamine (hereinafter referred to as the Product under Consideration (PUC) or the subject goods), originating in or exported from China PR and United Arab Emirates [UAE] (hereinafter referred to as the subject countries), and for initiation of antidumping investigation and levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
2. And whereas, the Authority found sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry; causal link between alleged dumping and injury and thus initiated the antidumping investigation in terms of Rule 5 of the Anti-dumping Rules vide Notification No. 14/16/2013-DGAD dated 25th March, 2014 to investigate into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry and to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed in this investigation:
 - (i) The Authority notified to the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the application of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.
 - (ii) The Authority issued a public notice No 14/16/2013-DGAD dated 25th March, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - (iii) The Authority forwarded a letter along with copy of the public notice to all the known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the AD Rules.

- (iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters in the subject countries in accordance with the AD Rules. A copy of the application was also made available to other interested parties, upon request.
- (v) Copies of the letter and the exporter's questionnaires sent to the exporters/producers in the subject countries were also sent to the Embassies of the subject countries in India along with a list of known exporters / producers with a request to advise the known exporters/producers from the subject countries as also other exporters / producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time limits.
- (vi) The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in China PR in accordance with the AD Rules:
 - a) Jinan Xiangrui Chemical Co. Ltd., No. 30 Jiefang Road, Jinan, Shandong, China
 - b) Ruixing Group Co. Ltd., Room A-102 Chemical Market, No. 96 South Gongye Road, Lixia District, China
 - c) Jinan Haoyang Chemical Co. Ltd., Hehua East Road, Mingshui, Zhangqui City, Shandong Province, China
 - d) Nanjing Tichem Industry Co. Ltd., 1804 Ruihua Mansion, 315 Zhongshan Nan Road, Nanjing, China
 - e) Jinan Shenyu International Trade Co. Ltd. - North Of Lishan, North Road, Jinan, Shandong, 250100, China
 - f) Anhui Graceman Imp. & Exp. Development Co., Ltd. The Garments Mansion, No. 112, Lujiang Road, Hefei, Anhui – 233500, China
 - g) Jin De Yuan Chemical Co., Ltd. Street No. 111 North 2nd Ring Road, Chang An Area, Shijiazhuang, Hebei, China
 - h) Jinan Licheng Xinxing Auxiliary Agent Factory, Lingang Development Zone, Yaoqiang Town, Licheng District, Jinan – 250100 - China
- (vii) None of the exporters from China PR filed responses to the questionnaire.
- (viii) The Authority did not send the exporter's questionnaires to any known exporters in UAE because the Domestic Industry did not provide the details of any known exporter in UAE. However, since the Domestic Industry had given prima facie evidence of dumped imports from UAE, the Authority had sent a letter to the embassy of UAE in New Delhi mentioning therein that “.....all exporters of the subject goods might not have been intimated directly by the Authority. It is, therefore, requested that this investigation may be brought to the notice of all concerned. Exporters/producers having interest in export of the subject goods to India may be advised to furnish information in the form and manner prescribed in the enclosed Questionnaire to the Authority within 40 days of the date of this communiqué”.
- (ix) None of the exporters from UAE filed responses to the questionnaire. However, legal submissions have been made by the Ministry of Economy, UAE.
- (x) The Authority also forwarded a copy of the public notice to the following known importers/users (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4).

Importers/Users

- (a) Shubham Chemicals & Solvents Ltd., Delhi
- (b) Ashoka Marketing Agencies, Chennai
- (c) Esterkote Pvt. Ltd., Chennai
- (d) Gargi Huttens P. Ltd -Albertus Pvt. Ltd., Mumbai
- (e) Saket Chemicals, Mumbai
- (f) Dujowala Paper Chem, Mumbai
- (g) IVP. Ltd., Jamshedpur
- (h) T.R. Chemicals Pvt. Ltd., Rajganpur, Orissa
- (i) HPL Industries Pvt. Ltd., Faridabad
- (j) Shivam Adhesives Pvt. Ltd., Hanumangarh Jn, Rajasthan
- (k) IVP. Ltd., Palghar, Thane
- (l) Foseco India Ltd., Pune
- (m) National Chemical Industries, Kota

- (n) Rajasthan Coatings & Chemicals, Jodhpur
- (o) Demaco Polymers P. Ltd., Faridabad
- (p) Indogulf Industries Ltd., New Delhi
- (q) Getwell Chem, Mumbai
- (r) Modichem Plast Materials P. Ltd., Mumbai
- (s) Rupani Chemical Agencies, Chennai
- (t) X 'Pro India Ltd., Faridabad
- (u) Ordnance Factory Nagpur
- (v) S.R. Plastics, Delhi
- (w) Resins & Plastics Ltd., Mumbai
- (x) Pragati Chemicals P. Ltd., Ankleshwar, Gujarat
- (y) D.C.Chemicals, Kolkata
- (z) Promis Industries, Jamshedpur
- (aa) P.Kumar & Co., Kolkata
- (bb) Techno Waxchem P. Ltd., Kolkata
- (cc) Dujadwal Paperchem, Mumbai
- (dd) National Techno Industries, Kota
- (ee) A.V.M. Sales Corpn., Kolkata
- (ff) Goodwill Rasayan, Mumbai
- (gg) United Meta Chem Pvt. Ltd., Pune
- (xi) None of the importers/users filed any responses to the questionnaire or made any submissions.
- (xii) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation was from 1st October, 2012 to 30th September, 2013. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.
- (xiii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and adopted for the purpose of the present investigation.
- (xiv) The Authority made available non-confidential version of the evidence in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per the AD Rules.
- (xv) The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- (xvi) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 5th January, 2015 which was attended by only the domestic industry. The domestic industry which presented its views in the oral hearing was requested to file written submissions of the views expressed orally. However, after the oral hearing, due to change in the incumbency of Designated Authority, another oral hearing was held on 19th August, 2015. This new public hearing was held by the new DA as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) vs Designated Authority, delivered by a Division Bench in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 7-1-2011. The new oral hearing was again attended by the domestic industry only. The Domestic Industry was again requested to file written submissions of the views expressed orally.
- (xvii) The submissions made by the domestic industry and the Government of UAE during the course of the investigation and considered relevant by the Authority have been examined and addressed in this investigation.
- (xviii) On the spot verification of the information and data submitted by the domestic industry was carried out to the extent deemed necessary.
- (xix) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined by the Authority with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims,

wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed. Wherever possible, the interested parties were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- (xx) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these essential facts on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.
- (xxi) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 08.09.2015. The post Disclosure Statement submissions were received only from the domestic industry and have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- (xxii) At the request of the Authority, the Central Government extended the time period to complete the investigation up to 24th September, 2015.
- (xxiii) *** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xxiv) The exchange rate adopted for the POI is 1 US \$ =Rs 56.89.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions by the Domestic Industry

- 4. The following submissions have been made by the domestic industry:
 - (i) The product under consideration in the present investigation is Hexa Methylene Tetramine, known as Hexamine in market parlance.
 - (ii) Hexamine is used for various industrial purposes. The most important use of Hexamine is for production of Solid Phenolic Resins. It is also being used in Thermosetting Resins like Phenolformaldehyde. It is used as a cross-linking agent for hardening and resins.
 - (iii) There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods exported from the subject countries. Both have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably.

C.2 Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

- 5. None of the other interested parties have responded or raised any issues with respect to the product under consideration and like article.

C.3 Examination by the Authority

- 6. The product under consideration in the present investigation is Hexa Methylene Tetramine known as Hexamine in market parlance. Hexa Methylene Tetramine is a white crystalline powder with a sweet metallic taste. In the pure form, it is colourless and odourless. It crystallizes in rhombic dodecahedrons. Hexa Methylene Tetramine compound is also known as Ammoform, Methenamine, Cystamine, Cystogen, Urotropine. It is classified under custom sub-heading 2921.29.10 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. With regard to the issue of Like Article, the Authority has examined the submissions on record and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and that imported into India from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties has raised any objection in this regard. In view of the same, the Authority holds the subject goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods imported from the subject countries in accordance with the AD Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Views of the Domestic Industry

- 7. The Domestic Industry has made the following submissions with respect to the scope of domestic industry and standing:
 - (i) The petition has been jointly filed by M/s Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd., Vadodara and M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd., Ankleshwar, on behalf of the domestic industry.

- (ii) There were four producers of the product in India. However, severe dumping of the product from a number of countries has led to the closure of production of the other two producers, namely, M/s. Rockhard and M/s Newton Engineering. Therefore, production of the petitioners constitutes total Indian production within the meaning of the Rules.

D.2 Views of exporters/importers/users and other opposing interested parties

8. None of the other interested parties has responded or raised any issues with respect to the scope of the domestic industry and its standing.

D.3 Examination by the Authority

9. The Authority has examined the submissions made. The petition was jointly filed by M/s Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd., Vadodara and M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd., Ankleshwar. Both the companies are producers of the product under consideration in India and as per the records available, they have not imported the product from the subject countries during period of investigation. They are not related to any producer in the subject countries or importer in India.
10. As per the information available with the Authority, the applicants account for a major proportion of Indian production of the subject goods and, therefore, constitute the domestic industry within the meaning of the Rules and have the standing.

E. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

E.1 Normal Value, Export Price and Dumping Margin

11. The Authority notes that none of the exporters/producers from the subject countries has responded to the initiation notification by filing exporter questionnaire in the manner and format prescribed.

E.2 Views of the domestic industry

12. The Domestic Industry has made the following submissions with respect to normal value, export price and dumping margin:
- (a) China should be considered a non-market economy in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- (b) AD Rules have prescribed certain conditions that have to be satisfied in order to establish the claim of market economy treatment (MET). Based on various pronouncements relating to examination of market economy status by India and other investigating authorities, certain jurisprudence has clearly emerged and market economy status cannot be granted unless following conditions are fulfilled. It is to be noted that each and every condition must be fulfilled by an intending exporter in order to claim market economy treatment.
- (i) Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
- (ii) Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.
- (iii) Market economy status cannot be given unless the responding exporter establishes that their books are audited in line with international accounting standards.
- (iv) Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied.
- (v) The onus/obligation to establish market economy status is onto responding Chinese exporters and not onto the Designated Authority.
- (vi) Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim.
- (vii) In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
- (viii) Except where the responding Chinese exporters confirm to each of these standards, the Designated Authority is required to determine normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the AD Rules.
- (c) It has been contended by the domestic industry that since none of the exporters or producers in the subject countries have responded to the initiation notification or filed any questionnaire responses, the Authority may proceed on the basis of best available information as per Rule 6(8).

- (d) India is an appropriate surrogate country for Chinese producers. This has been accepted by other investigating authorities also. Petitioners have claimed normal value in China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, for price and consumption norms of major raw material (Formaldehyde) and all other raw material costs, utility and conversion cost. In view of the significant increase in the raw material prices which has led to significant increase in the associated cost of the product; the petitioners have claimed construction of month-wise normal value to calculate month-wise dumping margin.
- (e) The petitioners have made efforts to get evidence of price of product concerned in the domestic market of UAE and to get evidence of price from published sources. However, they could not collect any information/evidence such as price lists or quotations of producers of the subject goods in the domestic market of UAE due to lack of relevant information in public domain and, therefore, they have constructed the normal value in the case of imports from UAE, based on the international prices of the raw material taken from DGCIS data and consumption norms of the domestic industry, estimates of conversion costs, selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin. In view of significant increase in the raw material prices, which has led to significant increase in the associated cost of the product, the petitioners have claimed consideration of month-wise normal value to calculate month-wise dumping margin.
- (f) Petitioners claim adjustment of expenses for ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, bank charges, commission and VAT (in case of China PR).
- (g) After considering the normal value and export price on the above basis, dumping margins for both the subject countries are significant.

E.3 Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

- 13. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members as well. Therefore, in terms of para 8 (2) of the Annexure I of AD Rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules.
- 14. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules, as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from China PR are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-
 - a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
 - d. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
- 15. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provides that:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

16. None of the exporters/producers from China PR has responded to the questionnaire pertaining to market economy status and to the exporters' questionnaire, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption.
17. In view of the fact that none of the producers/exporters has filed any exporter's questionnaire including MET questionnaire, MET status has not been accorded to Chinese producers. Further, none of the interested parties, including the domestic industry, has made available any material fact to the Authority to select an appropriate market economy third country. The Authority has, therefore, determined the normal value in respect of China PR on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.
18. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration for all exporters from China PR has been constructed based on facts available and the Authority has determined the normal value in respect of China PR on "any other reasonable basis", in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. Normal value at ex-factory level in respect of China PR is determined on the basis of constructed cost on month-wise basis keeping in view increase in the price of raw material. The normal value has been constructed on the basis of cost of production of the most efficient domestic producer by adopting international prices of the raw materials and allowing reasonable profit margin. The weighted average constructed normal value so determined is shown in the Dumping Margin Table below.

E.4 Determination of Normal Value for producers and exporters in UAE

19. The Authority notes that no questionnaire response has been filed by any producer/exporter from UAE. Therefore, the Authority is constrained to determine the Normal Value in respect of UAE as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, Normal value at ex-factory level in respect of UAE is determined on the basis of constructed cost on month-wise basis keeping in view increase in the price of raw material. The normal value has been constructed on the basis of cost of production of the most efficient domestic producer by adopting international prices of the raw materials and allowing reasonable profit margin. The weighted average normal value so determined is shown in the Dumping Margin Table below.

E.5 Determination of Export Price for producers and exporters in China PR

20. Since none of the exporters from China PR has responded to the Authority, the Authority has determined the export price in respect of imports from China PR on the basis of best information available in accordance with Rule 6(8) of the AD Rules. The petitioners have determined export price on the basis of imports of the product under consideration in India, as reported by IBIS, the data supplying agency. The Authority has also procured the transaction wise import data from the DGCI&S. It is seen that the prices of imports reported by both DGCI&S and IBIS are comparable. However, the volume of imports reported in DGCI&S is higher. The Authority has considered the data received from DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by applicant domestic industry in view of non cooperation from the exporters from China PR. Price adjustments have been made to account for ocean freight, marine insurance, bank charges, VAT, commission, port expenses and inland freight expenses before arriving at export price at ex-factory level. The ex-factory export price so determined is shown in the Dumping Margin Table below.

E.6 Determination of Export Price for producers and exporters in UAE

21. Since none of the exporters from UAE has responded to the Authority, the Authority has determined the export price in respect of imports from UAE on the basis of best information available in accordance with Rule 6(8) of the AD Rules. The applicants have determined export price on the basis of imports of the product under consideration in India, as reported by IBIS, the data supplying agency. The Designated Authority has also got the transaction wise import data from the DGCI&S. It is seen that the prices of imports reported by both DGCI&S and IBIS are comparable. However, the volume of imports reported in DGCI&S is higher. The Authority has considered the data received from DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by the applicant domestic industry in view of non cooperation from the exporters from UAE. Price adjustments have been made to account for ocean freight, marine insurance, bank charges, commission, port expenses and inland freight expenses before arriving at export price at ex-factory level. The ex-factory export price so determined is shown in the Dumping Margin Table below.

E.7 DUMPING MARGIN

22. Considering the normal values and export prices as determined above, the proposed dumping margin has been determined as follows. It is seen that the dumping margins are more than de-minimis and significant.

Dumping Margin Table

Items	Unit	China PR	UAE
Value	US\$/MT	****	****
Price	US\$/MT	****	****
Dumping Margin	US\$/MT	****	****
Dumping Margin %	US\$/MT	****	****
Dumping Margin %	%	5-15	5-15

*Calculated on Monthly basis

F. ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK**F.1 Views of the Domestic Industry**

23. The domestic industry has submitted that:

- (i) Imports of the product under consideration from the subject countries increased in absolute term and in relation to production and consumption in India over the injury period.
- (ii) Imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry to a significant extent.
- (iii) Imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping.
- (iv) Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of production, domestic sale, capacity utilization, inventories, market share, profits, return on investments, cash flow, and has reached negative levels.
- (v) Performance of the domestic industry was sub-optimal in respect of production and domestic sales.
- (vi) Dumping margin is significant.
- (vii) The factors affecting the prices of the domestic industry are import prices from the dumped sources. Thus, the price suppression is due to dumping of the product in the market.
- (viii) In addition to dumped imports from the subject countries, imports from existing sources attracting anti dumping duty are also causing injury.
- (ix) Growth of the domestic industry is adverse in terms of a number of parameters.

F.2 Views of the Other Interested Parties

24. The Ministry of Economy, UAE, has made the following submissions with respect to injury and causal link:

- a) Designated Authority is under a Due Process Obligation to provide full opportunities for UAE to defend its rights.
- b) Designated Authority must show that injury to the domestic like product is caused due to dumped products. Non confidential data shows a decrease in 2013 in absolute terms by 12% (1,239 MT in 2013 instead of 1,439 MT in 2012) and relative to domestic industry production by 1% as well as in relation to consumption of product under investigation by 1%. Therefore, it is unlikely that any other significant effect of import from subject countries on relevant economic factors and indices having bearing on state of domestic industry will be attributed to imports from the subject countries.
- c) UAE believes injury to the concerned domestic product has not been caused by imports from subject countries but other factors.
- d) During 2011-12 time frame in which volume increased from 331MT to 1,088 MT, the domestic industry ameliorated its performance in terms of capacity, production, employment, wages and domestic sales.
- e) There is significant increase in imports from countries attracting anti-dumping duties, which is causing the alleged injury to domestic industry. Iran, Russia and Kingdom of Saudi Arabia, although facing duties on Hexamine, have increased their exports in absolute terms by 77.5% and relative to domestic industry production by 4%.
- f) Market share of imports from countries attracting anti-dumping duties increased from 3.7% in 2012 to 7% in 2013 and for imports of product under investigation increased from 27% to 42% in 2013.
- g) Contraction in demand is causing the alleged injury to the domestic industry. POI data shows a decline in demand by 5.2% falling from 13,780 MT to 13,060 MT.

- h) Designated Authority is under WTO obligation to base its findings on positive evidence and involve an objective examination.

Post second oral hearing submissions

25. The post second oral hearing written submissions have been submitted only by the domestic industry and are repetitive, i.e., imports of the product under consideration from the subject countries increased over the injury period; the imports are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry; performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of production, domestic sales, capacity utilization, market share, profits, return on investments, cash flow etc.

Examination by the Authority

26. The Authority notes that the submissions of the domestic industry are repetitive and have been dealt in this Disclosure Statement at relevant headings.

F.3 Cumulative assessment

27. Annexure II para (iii) of the AD Rules which provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article, and
 - b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
28. In this regard, the Authority notes that:
- (i) The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
 - (ii) The volume of imports from each of the subject country is more than the limits prescribed above;
 - (iii) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

F.4 Examination by the Authority

29. In consideration of various submissions made by the domestic industry and other opposing interested party in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry.
30. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
31. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules supra.
32. With regard to various contentions raised by the other interested parties, the Authority notes as follows:
- (i) The Authority considers that it is under due process obligation to provide full opportunities for UAE to defend its rights. The Authority notes that all due process obligation under the Indian Rules and WTO obligations have been fully complied with in the present investigation. The Authority also notes that none of the UAE producer/exporter has cooperated with the Authority by filing questionnaire response.
 - (ii) As regards the argument that it is to be proved that injury to the domestic industry must be from dumped imports from UAE and imports of the product declined from UAE in absolute terms and in relation to production and consumption in India, the Authority notes that the injury analysis has been carried out cumulatively in respect of imports from China and UAE. It has not been contended by any party that cumulative assessment of injury to the domestic industry is inappropriate in the present case. Further, the Authority has considered 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI as the injury period in the present case and, therefore, any

analysis must be carried out by considering the injury investigation period. It would not be appropriate to selectively compare the POI with immediate preceding year.

- (iii) As regards the contention that injury to the domestic industry is because of other factors and not because of dumped imports, the Authority has examined the other factors listed under the law. The Authority has not come across any other factor which could have caused injury to the domestic industry at the same time, nor any interested party has established existence of any other factor that could have caused injury to the domestic industry.
- (iv) As regards the contention that domestic industry has suffered injury from dumped imports from other sources attracting anti dumping duty, the Authority notes that the injury from dumped imports from other sources is not required to be segregated under the Rules. The Indian Rules and WTO Agreement clearly require the Designated Authority to segregate injury suffered by the domestic industry from the volume and price of undumped imports.
- (v) As regards the contention that the Authority is under WTO obligation to base its findings on positive evidence and involve an objective examination, the Authority notes that WTO obligation has been duly complied with.
33. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd. and M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd., constituting domestic industry, under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

A. Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

a) Assessment of Demand and Market Share

34. The Authority has determined demand as the sum of domestic sales of Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources. The demand so assessed can be seen in the table below:

Demand into India		2010-11	2011-12	2012-13	POI
Sales of Domestic Industry	MT	10,453	11,550	11,849	10,905
Imports- Subject Countries	MT	409	1,270	1,343	1,300
Imports-Countries attracting ADD	MT	727	600	575	1,108
Imports-Other Countries	MT	0	241	44	264
Total Demand	MT	11,589	13,661	13,811	13,577
Market Share:					
Domestic Industry	%	90.19%	84.55%	85.80%	80.32%
Subject Countries	%	3.53%	9.29%	9.72%	9.58%
Countries attracting ADD	%	6.28%	4.39%	4.16%	8.16%
ountries	%	0.00%	1.76%	0.32%	1.94%

**POI – October 2012-September 2013*

35. The Authority notes that the demand for the product concerned in the country has increased from the base year to the 2012-13 and then declined slightly in the POI. However, the demand in the POI has increased as compared to the base year. The sales of the domestic industry have also increased up to 2012-13 and then declined in the POI. Imports from the subject countries have also shown a similar trend.
36. It is seen from the table above that the market share of domestic industry has declined over the injury period, whereas that of imports from the subject countries as well as countries attracting anti dumping duty has increased as compared to base year.
- b) Volume Effects of Dumped Imports: Import volumes and market shares**
37. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Volume of imports and imports in relation to production and consumption in India are given in the table below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Imports-China	MT	409	750	494	640
Imports-UAE	MT	0	520	849	660
Imports – Subject countries	MT	409	1,270	1,343	1,300
Imports –Countries attracting ADD	MT	727	600	575	1,108
Imports – Other countries	MT	0	241	44	264
Total Imports	MT	1,136	2,111	1,962	2,672
Share of imports from subject countries in relation to					
Total Imports	%	35.99%	60.15%	68.44%	48.65%
Consumption	%	3.53%	9.29%	9.72%	9.58%
Production	%	3.79%	10.03%	10.94%	11.02%

38. The Authority notes that:

- (i) Imports of the subject goods from UAE started in 2011-12 and remained significant over the injury period. Imports from China PR increased gradually over the injury period.
- (ii) Even though the volume of imports from the subject countries on cumulative basis declined in POI, the same is still quite significant and higher than the volume of imports in 2010-11 and 2011-12.
- (iii) The subject imports have increased not only in absolute terms but also in relation to production and consumption in India with a marginal decline in the POI.
- (iv) Even though the imports in relation to production and consumption declined in POI, the same is still quite significant and higher than the imports in relation to production and consumption in 2010-11 and 2011-12.
- (v) As regards the argument that since imports did not increase either in absolute terms or in relation to production or consumption and it is unlikely that any other significant effect of import from subject countries on relevant economic factors and indices having bearing on state of domestic industry will be attributed to imports from the subject countries, or the domestic industry ameliorated its performance in terms of capacity, production, employment, wages and domestic sales when imports from UAE have shown an increase, the Authority notes that overall performance of the domestic industry shows material deterioration over the injury period.

B. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

a) Price Undercutting and Price Underselling

39. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of subject goods of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury and, thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows.

Price Undercutting

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Net Sales Realization	Rs/MT	****	****	****	****
Landed Value of Imports – China	Rs/MT	48,530	55,042	70,926	68,173
Landed Value of Imports – UAE	Rs/MT	0	52,629	65,076	57,671
Landed Value – Subject countries as a whole	Rs/MT	48,530	54,053	67,226	62,841
Price Undercutting – China	Rs/MT	****	****	****	****
Price Undercutting – UAE	Rs/MT	****	****	****	****
Price Undercutting – Subject countries as a whole	Rs/MT	****	****	****	****
Price Undercutting – China	%	****	****	****	****
Range	%	0-10%	5-15%	(0-10)%	0-10%
Price Undercutting – UAE	%	****	****	****	****
Range	%	-	10-20%	0-10	15-30%
Price Undercutting – Subject countries as a whole	%	****	****	****	****
Range	%	0-10%	10-20%	0-10%	5-15%

Price Underselling

Particulars	Unit	China	UAE
Non-injurious Price	USD/MT	****	****
Landed Value of Imports	USD/MT	1,199.60	1,022.58
Price Underselling	USD MT	****	****
Price Underselling	%	****	****
Price Underselling Range	%	0-10	15-25

40. The Authority notes that price undercutting from both the subject countries is quite substantial. It is further noted that the landed value of imports from the subject countries is also substantially below the non-injurious price of the domestic industry, thereby, resulting in significant price underselling effect as would be seen from the price underselling level on weighted average basis which is calculated on month-wise basis keeping in view significant increase in the raw material prices, which has led to significant increase in the associated costs and prices of the product.

b) Price Suppression and Depression

41. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales. The data shows that the domestic industry's selling price has remained below its cost of sales from 2011 onwards till the POI, signifying existence of price suppression effect. The trends in this regard are summarized below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Net Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>135</i>	<i>139</i>
Cost of Sales	Rs./MT	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>141</i>	<i>154</i>	<i>163</i>
Landed Value of Imports					

China	Rs./MT	48,530	55,042	70,926	68,173
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>146</i>	<i>140</i>
UAE	Rs./MT	0	52,629	65,076	57,671
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	-	<i>100</i>	<i>124</i>	<i>110</i>

42. The Authority notes that the selling price has increased throughout the injury period. However, the increase is not proportionate to the increase in the cost of sales over the same period. The petitioners have claimed that there has been significant increase in the raw material cost which has led to significant increase in the cost of production over the injury period. Further, the selling price of the domestic industry was below the cost of sales from 2011-12 onwards till the POI. The landed value of imports from the subject countries during the injury period has also increased in comparison to the base year. However, the increase in landed value is lower than the increase in the cost of sales and the selling price. Further, the landed value of imports is below the cost of sales in 2011-12, 2012-13 and the POI. Thus, it is noted that dumped imports are suppressing the domestic prices of domestic industry.

C. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

43. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

44. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

45. The information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry is as under.

rs	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
	MT	10,800	17,600	17,600	7,600
on	MT	10,779	12,660	12,273	1,800
Utilization	%	99.80%	71.93%	69.73%	7.04%
Sales	MT	10,453	11,550	11,849	0,905
	MT	11,589	13,661	13,810	3,577

46. The Authority notes that the domestic industry increased its installed capacity for the production of the product concerned in 2011-12. The production of the domestic industry has increased till 2011-12, and then declined in 2012-13 and POI. It is noted that despite addition of capacities, the domestic sales volumes have declined in the POI. Further, the capacity utilization of the domestic industry declined over the injury period. Thus, production, domestic sales volumes and capacity utilization have declined in the POI.

47. The petitioners have claimed that the domestic industry could have achieved capacity utilization levels in the POI as were achieved in the past. The volume of production achieved by the domestic industry was lower than what the domestic industry could have produced had there not been dumped imports. Thus, the imports are clearly showing adverse volume effect.

48. The petitioners further claimed that considering the demand for the product under consideration and capacities with the domestic industry, there was no need for any imports in the country and the domestic industry could have met entire demand in the market. However, the foreign producers resorted to dumping, which has caused injury to the domestic industry.

b) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit

49. The profits, return on investment and cash flow of the domestic industry have been examined as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of Sales	Rs./MT	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>141</i>	<i>154</i>	<i>163</i>
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>135</i>	<i>141</i>
Profit/Loss (per unit)	Rs./MT	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>-62</i>	<i>-55</i>	<i>-77</i>
Profit/loss total	Rs. Lacs	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>-69</i>	<i>-62</i>	<i>-80</i>
Profit before interest	Rs. Lacs	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>-47</i>	<i>-37</i>	<i>-49</i>
Cash Profit	Rs. Lacs	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>-52</i>	<i>-45</i>	<i>-61</i>
Return on Investment	%	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>-27</i>	<i>-19</i>	<i>-24</i>

50. The Authority notes from the above that:

- (i) Both the selling price and cost of sales of the domestic industry have increased over the injury period. However, the increase in selling price was less than increase in costs. This has led to significant decline in profitability and eventually to a situation of financial losses since 2011-12.
- (ii) Profit before interest, cash profit and return on investment have declined significantly over the injury period and follow the same trend as that of profits.
- (iii) The petitioners have claimed that with continuous presence of dumped imports in the Indian market, the domestic industry, in order to survive in the market, was left with no option but to sell the goods at prices below cost. The domestic industry was prevented from raising its prices in proportion to increase in costs.
- (iv) It is noted from the above information that the domestic industry has been suffering injury in terms of profit-related parameters. The position of the industry with respect to these parameters has deteriorated substantially in the period of investigation.

c) Employment, Wages and Productivity

51. The status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Employment	Nos.	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>130</i>	<i>128</i>
Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>135</i>	<i>144</i>
Wages per MT of production	Rs.	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>118</i>	<i>132</i>
Productivity per Employee	MT	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>87</i>	<i>86</i>

52. It is noted from the above that the number of employees has increased over the injury period. Productivity per employee has declined with decline in production. Further, the wage cost per unit has increased. The petitioners have claimed that given the fact that the constituents of the domestic industry are multi product companies, these parameters may not show current and potential adverse impact of dumping.

d) Inventories

53. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry which is given in the following table.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Average Inventory	MT	****	****	****	****
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>203</i>	<i>317</i>	<i>439</i>

54. It is noted from the above table that the average inventory in absolute term shows a rising trend. The average inventory has increased by more than four times during POI. The petitioners have claimed that this is in view of severe dumping from the present and existing sources.

e) Magnitude of Dumping

55. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined by the Authority against the subject countries is above *de minimis* and significant.

f) Ability to raise capital

56. The petitioners have argued that the constituents of the domestic industry are multi product companies. Ability to raise investments is reflective of overall business operations and is not dependent on particular product performance.

g) Growth

57. With regard to the growth of the domestic industry, the position is as under:

Year by Year)		010-11	011-12	012-13	OI
Production Volume	%	-	17.45	-3.06	.85
Domestic Sales Volume	%	-	10.50	2.59	.97
Profit/Loss	%	-	162.31	-11.90	0.46
Return on Capital Employed	%	-	****	****	***
Market Share	%		5.64%	1.25%	48%

58. The Authority notes that the domestic industry has registered a negative growth in terms of volume as well as price parameters such as production, sales volume, cash profit and return on investments. The profitability has declined as can be seen from parameters such as profits, cash profits and return on investments. Further, capacity utilization, market share and inventory level shows negative growth. Overall growth of the domestic industry over the injury period was adverse.

h) Factors Affecting Domestic Prices

59. The examination of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as price underselling in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the POI and, therefore, it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from the subject countries and other dumping countries.

60. It is noted from the information provided by the applicants that the cost of sales increased by 63% during the POI as compared to base year. Further, the raw material cost alone has increased by 60% in the POI as compared to base year. However, the export price from UAE increased by only 11% during POI as compared to 2011-12, as there were no imports from UAE in the base year. Further, the export price from China increased by 39% during POI as compared to the base year.

Conclusion on injury

61. From the foregoing, it is concluded that imports of the product under consideration from the subject countries increased in absolute term and in relation to production and consumption in India over the injury period. Imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry to a significant extent. Imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of production, domestic sale, capacity utilization, inventories, market share, profits, return on investments, cash flow and has reached negative levels. Performance of the domestic

industry was sub-optimal in respect of production and domestic sales. Dumping margin is significant. The factors affecting the prices of the domestic industry are import prices from the dumped sources. Thus, the price suppression is due to dumping of the product in the market. In addition to dumped imports from the subject countries, imports from existing sources attracting anti dumping duty are also causing injury. Growth of the domestic industry is adverse in terms of a number of parameters.

62. It is thus seen that there has been a significant increase in the dumped imports, both in absolute terms and relative to production or consumption in India. There has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India and the effect of such dumped imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree. Consequent impact of the dumped imports on the domestic industry was adverse as established by collective and cumulative assessment of various relevant economic factors and indices such as sales, profits, production, market share, productivity, return on investments, utilization of capacity, factors affecting domestic prices, magnitude of the margin of dumping, cash profit (cash flow), inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. It is, thus, proposed to conclude that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumping from China and UAE coupled with dumping from existing sources.

F.5 Other Known Factors and Causal Link

63. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:
- (a) Contraction in demand and / or change in the pattern of consumption
64. The Authority notes that demand for the product has grown over the injury period, except a slight decline in the POI. However, demand for the product under consideration has increased in the POI as compared to the base year. Hence, a decline in demand cannot be causing injury to the domestic industry. Further, the Authority has found no evidence of a change in the pattern of consumption of the product.
65. As regards the contention that demand for the product declined and has also caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the overall demand for the product has shown an increase. Slight decline in demand in the POI as compared to immediate preceding year cannot be termed as decline in demand. Market share of subject countries increased from 3.53% to 9.58% over the injury period, whereas market share of the domestic industry declined from 90.19% to 80.32% over the injury period.
- (b) Volume and Prices of imports not sold at dumped prices
66. The Authority notes that apart from the subject countries, imports of Hexamine are entering the country from Saudi Arabia and Russia (attracting anti dumping duty).
- (c) Trade restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers
67. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject countries compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.
- (d) Developments in Technology
68. The Authority notes that there are no developments in technology with respect to the product or its manufacture that could have resulted in the injury caused to the domestic industry.
- (e) Export performance
69. The export performance of the DI is given in the Table below. However, information relating to injury has been examined separately for domestic operations to the extent possible and, therefore, export performance of the domestic industry is not a possible cause of the injury determined.

Particulars		2010-11	2011-12	2012-13	POI
Export Sales	MT	****	****	****	****

(f) Productivity of the domestic industry

70. The Authority notes that productivity of the domestic industry has declined because of the inability of the domestic industry to increase production as a result of dumping. Hence, a decline in productivity cannot be a direct cause for the injury suggested by the DI.

(g) Performance of other products

71. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury found, since all parameters were examined with respect to the product under consideration.
72. The Authority notes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.
- (i) The dumped imports from the subject countries have entered the Indian market in significant volume and increased over the injury period.
- (ii) Subject imports are available at prices lower than domestic prices. Consequently, the consumers are increasingly switching over to imports, thus, forcing the domestic industry to offer sub-optimal prices. There has been substantial price undercutting from the imports from China PR and UAE.
- (iii) Domestic sales have not been able to keep pace with the demand and the domestic industry has been losing out on its market share.
- (iv) The imports are occurring at dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry. Consequently, the domestic industry has suffered injury on account of profits, return on investment and cash flow.
- (v) The domestic industry is faced with price suppression in the market due to dumped imports.

F.6 Conclusion on Injury and Causation

73. The Authority notes that there has been an increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms and relative to apparent consumption and production in India. Production and sales volume of the domestic industry have declined over the injury period. Profit-related parameters of the domestic industry have all been significantly adverse. The level of inventories has been significantly high in the POI.
74. The Authority notes that the domestic industry was suffering injury on account of dumping of the subject goods from other countries even before imports from China and UAE commenced. There have been investigations conducted and anti dumping duties imposed on these imports. However, due to the price undercutting and price suppression specifically found in this investigation, it is clear that imports from the subject countries are also causing injury to the domestic industry in addition to the other existing sources.

F. 7 Magnitude of injury and injury margin

75. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry, taking into consideration the cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports from the subject countries to determine injury margin. The injury margin has been worked out as follows:

Injury Margin

Particular	Unit	China	UAE
Non Injurious Price (NIP)	US \$ /MT	****	****
Landed Value	US \$ /MT	1,199.60	1,022.58
Injury Margin	US \$ /MT	****	****
Injury Margin %	%	****	****
Injury Margin Range		0-10	15-25

76. The level of injury margins, as proposed to be determined, are considered significant.

G. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES**G.1 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties**

77. None of the exporters/importers/users and other opposing interested parties has made any post Disclosure Statement submissions.

G.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

78. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

- (a) Product under consideration is exported to India below its normal value resulting in dumping from the subject countries.
- (b) Both dumping margin and injury margin in the Period of Investigation are significant and positive from the subject countries.
- (c) Domestic Industry has suffered material injury.
- (d) The anti dumping duty is required to be imposed definitively in fixed form and the duty expressed in US\$ terms.

G.3 Examination by the Authority

79. The Authority has reached to the conclusion that the above arguments of the domestic industry are repetitive and have already been dealt with by the Authority in the Disclosure Statement earlier and have also been dealt with again in the Final Findings Notification under appropriate headings.

H. CONCLUSION

80. The Authority notes that none of exporters from China PR and UAE and importers/users and other opposing interested parties in India filed Questionnaire response. However, legal submissions have been submitted by the Ministry of Economy, UAE. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the domestic industry and the Ministry of Economy, UAE and facts available before the Authority and on the basis of above analysis and post Disclosure Statement submissions made by the Domestic Industry, the Authority concludes that:

- (a) Both dumping margin and injury margin in the Period of Investigation are significant and positive from the subject countries.
- (b) Domestic Industry has suffered material injury.

I. RECOMMENDATION

81. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and causal link thereof and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

82. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

S. No	Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of measurement	Currency
1	2921.29.10	Hexamine	China PR	China PR	Any	Any	84.25	MT	US\$
2	2921.29.10	Hexamine	China PR	Any other than China PR	Any	Any	84.25	MT	US\$
3	2921.29.10	Hexamine	Any other than subject countries	China PR	Any	Any	84.25	MT	US\$
4	2921.29.10	Hexamine	UAE	UAE	Any	Any	113.05	MT	US\$
5	2921.29.10	Hexamine	UAE	Any other than UAE	Any	Any	113.05	MT	US\$
6	2921.29.10	Hexamine	Any other than subject countries	UAE	Any	Any	113.05	MT	US\$

Explanation: Where there is overlapping of antidumping duty on the subject goods with respect to a subject country in different customs notifications, the duty applicable to that subject country shall be the one imposed under the customs notification in which the said country has been specifically mentioned under the Column “Country of Origin”.

83. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

84. An appeal against the order of the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Designated Authority